सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

आश्रय

त्रैमासिक न्यूजलेटर

सबका सपना, घर हो अपना

प्रधानमंत्री आवास योजना–
सबके लिए आवास (शहरी)

"प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास के विजन को पूरा करने के लिए एक कदम"

~ नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खण्ड 2, अंक 2, अप्रैल – जून 2017, नई दिल्ली

पीएमएवाई (शहरी) – सबके लिए आवास पर राष्ट्रीय समीक्षा/परामर्श

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्ववर्ती हुपा मंत्रालय) द्वारा नई दिल्ली में 12–13 अप्रैल, 2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (यू) मिशन में सम्मिलित सभी राज्यों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा /परामर्श आयोजित की गई ।

श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय आवासन और शहरी कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बैठक का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने तीन पुस्तिकाएं (प्रौद्योगिक उप–मिशन, क्षमता निर्माण और सामाजिक लेखा परीक्षा) भी जारी की। इस अवसर पर तीन टीवी विज्ञापन भी शुरू किए गए।

बैठक के दौरान पीएमएवाई (यू) के प्रमुख केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों ने मिशन की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया और संरचित चर्चाओं में भाग लिया। समीक्षा बैठक में अनुभव साझा करने और क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से सीखने के अवसर भी प्रदान किए गए ।

बैठक में 31 मार्च 2017 तक पीएमएवाई (यू) की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया :

- दिल्ली के अलावा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पीएमएवाई (यू) को लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 27,879 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता के लिए 17.73 लाख घरों को स्वीकृत किया गया है। । इसमें 93,473 करोड़ रुपये का कुल निवेश शामिल हैं । इसमें ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत 28,442 लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी के रूप में दिये गए 523.61 करोड़ रू. शामिल हैं।
- मिशन में (सीएलएसएस को छोड़कर) शीर्ष तीन निष्पादनकर्ता राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं।

- सीएलएसएस के तहत शीर्ष पांच निष्पादनकर्ता राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान हैं ।
- पीएमएवाई (यू) में अपनाने के लिए 16 नई उभरती हुई निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है। भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने नेल्लोर में प्रदर्शन आवास परियोजना और सामुदायिक केंद्र का निर्माण पूरा किया और भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, हैदराबाद और लखनऊ में चार प्रदर्शन आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
- मंत्रालय ने राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (एसएलटीसी) और शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सीएलटीसी) के तहत 2,420 विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए लगभग 50 करोड़ रु. जारी किए हैं।

माननीय मंत्री द्वारा राज्यों में पीएमएवाई (यू) की पुनरीक्षा

स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत के साथ पीएमएवाई (यू) मिशन दिनांक 25 जून, 2017 को 2 वर्ष पूरा कर चुका है। अन्य स्कीमों के साथ इस मिशन की प्रगति का स्टॉक लेने के लिए माननीय मंत्री (आवासन और शहरी कार्य) ने 3 महीनों में 11 राज्यों की पुनरीक्षा की है। पुनरीक्षा बैठकें राज्य की राजधानियों में संबंधित मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई थीं ।

इन पुनरीक्षा बैठकों का परिणाम बहुत लाभकारी हुआ है। माननीय मंत्री ने प्रत्येक राज्य में स्वीकृत आवासों का निर्माण पूरा वर्ष 2022 तक करने के लिए राज्यों से मौजूदा अवरोध को कम करने पुनरीक्षा की है । उन्होंने आगे की कार्यनीति और आवासों के निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए कार्यनीति पर भी चर्चा की । आने वाले महीनों में शेष राज्यों में प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए कुछ और बैठकें आयोजित की जाएगी ।

माननीय मंत्री ने पुनरीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के तीन मंत्रों – सुधार, कार्यान्वयन और परिवर्तन पर जोर देते हुए कहा कि देश का विकास राज्यों की प्रगति पर निर्भर करता है ।

माननीय मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले 3 महीनों के दौरान 22 राज्यों अर्थात – असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की प्रगति की पुनरीक्षा की है । गुजरात राज्य की पुनरीक्षा इसके पूर्व नवंबर, 2016 में की गई थी ।

जिन राज्यों की पुनरीक्षा की जानी है : आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, तेलगांना और प.बंगाल, और संघ राज्य क्षेत्र जिनकी पुनरीक्षा की जानी है : दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ।

18 अप्रैल, 2017 को गुवाहटी में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों की समीक्षा

2 मई, 2017 को बंगलुरू में आयोजित कर्नाटक की समीक्षा

19 मई, 2017 को रांची में आयोजित झारखंड की समीक्षा

26 मई, 2017 को रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ की समीक्षा

29 जून , 2017 को देहरादून में आयोजित उत्तराखंड की समीक्षा

पीएमएवाई (यू) की प्रगति

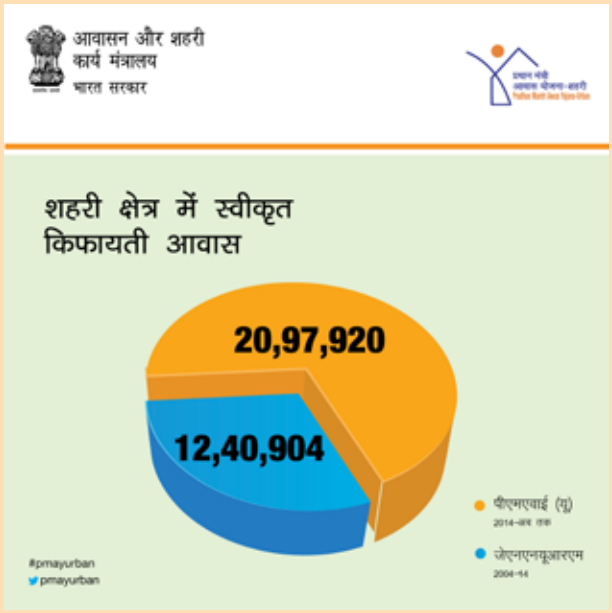

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठकें

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में और अन्य संबंधित विभागों के सदस्यों के साथ पीएमएवाई (यू) के लिए एक निर्णय निर्माता निकाय है। सीएसएमसी के मुख्य कार्यों में केन्द्रीय सहायता जारी करने, इस मिशन की समग्र समीक्षा और निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति आदि शामिल है।

अप्रैल–जून, 2017 की तिमाही के दौरान 03 सीएसएमसी बैठकें आयोजित की गई जिनमें भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और स्वस्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटकों के अंतर्गत कुल 1149 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 15 राज्यों से 3,14,106 आवासों को स्वीकृत किया गया।

जैसा कि उपरोक्त में स्वीकार किया गया है, 3.14 लाख आवासों के लिए 4,696.21 करोड़ रूपए शामिल हैं।

23 जून, 2017 को आयोजित पीएमएवाई (यू) के दो वर्ष पूरे होने पर समारोह

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), सबके लिए आवास मिशन 25 जून, 2015 को शुरू हुआ जिसमें भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अर्थात् वर्ष 2022 तक भारत के शहरी गरीबों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की कल्पना की गई है।

पीएमएवाई (यू) ने 25 जून, 2017 को दो वर्ष पूरे कर लिए। शहरी मिशनों–पीएमएवाई (यू) मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत मिशन के दो वर्ष मनाने के लिए "शहरी परिवर्तन, सीख और आगे का रास्ता" के बारे में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दो वर्षों में इन मिशनों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई।

राव इन्द्रजीत सिंह, माननीय राज्य मंत्री ने राज्यों में सफलता के वृतांतों और उत्तम पद्धतियों, और अखिल भारत बीएलसी लाभार्थियों के लिए एक पास बुक और टीपीक्यूएम दिशानिर्देशों का संकलन शुरू किया।

पीएमएवाई (यू) मिशन के सीएलएसएस घटक के संबंध में राज्यों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए प्रायासों को स्वीकार करने के लिए सीएलएसएस पुरस्कार समारोह को आयोजित किया गया। इस मिशन के सीएनए में से एक होने के नाते राष्ट्रीय आवास बैंक ने पुरस्कार समारोह का मार्गदर्शन किया।

पीएमएवाई(शहरी) समारोह के दो वर्षों की झलक

पीएमएवाई(शहरी) समारोह के दो वर्षों की झलक

प्रेस सम्मेलन

माननीय मंत्री ने 20 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में पीएमएवाई (यू) पर एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मीडिया को सम्बोधित किया। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान माननीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने पिछले दस वर्ष में किए गए कार्य की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी कुछ किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि यह लोगों द्वारा यथावांछित "विशिष्ट सरकार" है।

माननीय मंत्री जी ने मीडिया के साथ 13 जून, 2017 को वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान परस्पर बातचीत की । माननीय मंत्री ने गत तीन वर्षों में शहरी मिशनों की प्रगति को संकलित करते हुए एक पुस्तिका का विमोचन किया। एक छोटी–सी अवधि में शहरी गरीबों के लाभ के लिए लगभग 21 लाख किफायती आवासों के निर्माण के लिए अनुमोदन तथा ऐतिहासिक आरईआरए अधिनियम ने वर्ष 2016 में इसको एक वास्तविकता बनाया। यह तीन वर्षों की मुख्य विशिष्टता रही है।

भारत यू.एन-पर्यावास का अध्यक्ष निर्वाचित

भारत 10 वर्ष बाद यू.एन–पर्यावास का सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुआ । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) का यह संगठन विश्व भर में सामाजिक और पर्यावरणीय सुस्थिर मानव व्यवस्थापन को बढ़ावा देता है । निर्वाचित होने पर, श्री एम. वेंकैया नायडु, आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने ट्वीट किया, ''यू.एन–पर्यावास की शासी परिषद् के अध्यक्ष के रूप में चयन पर प्रसन्नता हुई। नए शहरी भविष्य के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है ।''

1978 में, यू.एन–पर्यावास की स्थापना से 1998 और 2007 के बाद इस महत्वपूर्ण संगठन की अगुवाई करने के लिए भारत का निर्वाचन तीसरी बार हुआ है ।

शासी परिषद् में 58 राष्ट्र सदस्य हैं जो 5 क्षेत्रीय ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

यू.एन–पर्यावास की शासी परिषद् के उद्देश्य हैं :–

- मानव बसावों के सामूहिक और व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना;
- मानव बसावों की समस्या से जूझ रहे देशों और क्षेत्रों की सहायता करना;
- मानव बसावों के मुद्दों पर सभी देशों में सह–सहयोग और सह–भागीदारी को सुदृढ़ करना ।

माननीय मंत्री जी ने ट्वीट द्वारा शासी परिषद् का धन्यवाद करते हुए कहा – ''मैं यूएन पर्यावास की शासी परिषद् के सदस्य देशों का भारत में विश्वास व्यक्त करने और मुझे अपना अध्यक्ष निर्वाचित करने पर धन्यवाद देता हूँ #जीसी26'' ।

इस बात पर टिप्पणी करते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि श्री नायडु अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और भावी शहरों के सृजन में अपना योगदान करेंगे । प्रधान मंत्री ने ट्वीट किया ''बधाई वेंकैया जी । मैं आश्वस्त हूं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और भावी शहरों के सृजन के लिए आप अपना योगदान देंगे ।''

8 मई से 12 मई, 2017 तक नैरोबी कीनिया में आयोजित यू. एन–पर्यावास की 26वीं शासी परिषद् का मुख्य विषय, ''नई शहरी

यूएन–पर्यावास की 26वीं शासी परिषद और एपीएमसीएचयूडी की ब्यूरो बैठक की झलक

यूएन–पर्यावास की 26वीं शासी परिषद के अवसर पर बैठकों की झलक

कार्य सूची के प्रभावी कार्यान्वयन के अवसर'' था जिसमें उप–विषय थे –

(i) बेहतर भविष्य के लिए समावेशी, सुस्थिर और पर्याप्त आवास, (ii) सुस्थिर शहरीकरण के लिए सहयोग और वित्तपोषण, और (iii) एकीकृत मानव बसाव, सुस्थिर शहरीकरण के लिए योजना।

पिछले वर्ष क्विटो, इक्वाडोर में विश्व समुदाय द्वारा एक नयी शहरी कार्यसूची अपनायी गई थी ।

नैरोबी, कीनिया में 8–12 मई, 2017 को यू.एन–पर्यावास की 58 सदस्यीय शासी परिषद् की 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय मंत्री महोदय ने तेज गति से बढ़ रहे शहरीकरण, विशेषकर, विकासशील देशों में, के संदर्भ में लोगों के रहन–सहन की मर्यादा और पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों की योजना और निष्पादन शहरोन्मुखी करने की आवश्यकता है ।

उन्होंने, सामूहिक, समावेशी और सुस्थिर शहरी विकास के भारतीय मॉडल के विभिन्न नए मिशनों पर प्रकाश डालते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास (पीएमएवाई–एचएफए), दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एनयूएलएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (ह्रदय) और स्वच्छ भारत मिशन पर विस्तार से बताया । उन्होंने कहा कि ये मिशन समाभिरूपता मोड में किफायती आवास सहित विभिन्न प्रकार की अवसंरचनात्मक समस्याओं का समाधान करते हैं ।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शहरी विकास संबंधी मिशनों को आगे और विशेष कार्यक्रमों से समर्थन प्राप्त होता है जैसे मेक–इन–इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्ट–अप–इंडिया, इन सबका लक्ष्य शहरों को आर्थिक विकास और सशक्तिकरण के अगुवा के रूप में पुनउर्त्साहक और पुनर्क्रियाशील बनाना है जिससे वे जीवन की संवर्धित गुणता के केन्द्र बन सकें ।

माननीय मंत्री ने आवासन और शहरी विकास पर 'एशिया प्रशांत मंत्री ब्यूरो बैठक'' की भी अध्यक्षता की । छठें एपीएमसीएचयूडी सम्मेलन के मेजबान के रूप में, भारत, 2018 की दूसरी छमाही में तेहरान में आयोजित होने वाली आगामी सम्मेलन तक अगले दो वर्षों के लिए, अध्यक्ष रहेगा ।

सफलता की कहानियां

कोच्ची, केरल

जानकी बालन, 82 वर्ष अपने पुत्र मणि, पोते निविन और उनकी पत्नी और बच्चे के साथ कोच्चि नगर निगम के डिवीजन 63 की गांधीनगर कॉलोनी में एक छोटे अर्ध पक्के मकान में रहती है। वे इस कॉलोनी में पिछले 40 वर्षों से रह रही है।

लगभग एक वर्ष पहले उन्हें नगर निगम द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे पीएमएवाई (यू) मिशन के बारे में पता चला। उन्हें डिवीजन द्वारा किए गए मांग सर्वेक्षण में शामिल किया गया। इससे पहले, जब उन्होंने पीएमएवाई (यू) शुरू होने से पहले आवास ऋण के लिए आवेदन किया था, उन्हें इस आधार पर ऋण देने से मना कर दिया कि उनकी भूमि एक कॉलोनी के बीच में है और यह भी कि उनके परिवार की कोई नियमित आय नहीं है। उनका पुत्र और पौत्र दोनों कुली का कार्य कर रहे थे जो ऋण के अनुमोदन हेतु बैंक के लिए संतोषजनक नहीं था।

पीएमएवाई (यू) मिशन के अंतर्गत सीएलएसएस घटक के बारे में जानने के पश्चात, उन्होंने 6 लाख रूपए के बैंक ऋण के लिए आवेदन किया जो मंजूर हो गया शेष 1 लाख रूपए उनकी अपनी बचत से लिए गए।

बैंक से प्रमुख वित्तीय सहायता और भारत सरकार से सब्सिडी की सहायता से उन्होंने 550 वर्ग फुट क्षेत्रफल का पक्का मकान बनाया है। मिशन ने उन्हें बेहतर और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर प्रदान किया है।

अहमदाबाद, गुजरात

अंजूबेन बाबूभाई परमार, 20 वर्ष, अहमदाबाद की रहने वाली हैं और 7,000 रूपए मासिक आय सहित पेशे से नर्स हैं। पांच सदस्यों के परिवार में वे तीसरी हैं, उनकी मां सविताबेन परमार एक विधवा हैं जिन्होंने अपने चार बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई है जिनमें से दो का विवाह भी किया है। वे सब्जियां बेचकर प्रतिमाह लगभग 15,000 रूपए अर्जित करती हैं।

वर्तमान में, मां–बेटी दोनों एक किराए के मकान में रहती हैं और प्रतिमाह 2500 रूपए किराए के रूप में देती हैं। उन्हें पीएमएवाई (यू) मिशन के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत 5.83 लाख रूपए का ऋण मंजूर किया गया और 2.08 लाख रूपए सब्सिडी प्राप्त हुई। वे शीघ्र ही अपने नए मकान में चली जाएंगी।

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (सबके लिए आवास)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा सं0–116, जी विंग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110011

दूरभाष: 011–23061419; फैक्स: 011–23061420
ई–मेल : jshfa-mhupa@gov.in
वेबसाईट : http://mhupa.gov.in
Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India
twitter.com/mohupa